

अधिनियम, 1995



विधि नं० एस. उ. प्र. वि. 889

नियमन नं० 30 पी०-41

लाइसेंस टू पोस्ट एंड क... न... र...

सरकारी गैजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

सबनऊ, मंगलवार, 8 अगस्त, 1995

श्रावण 17, 1917 शक सम्बत

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

पर्या 1477/सत्रह-वि०-1-1 (क) 12/95
सबनऊ, 8 अगस्त, 1995

औपसूचना

विविध

"म. का संशोधन" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधियम, 1995 पर दिनांक 4 अगस्त, 1995 को प्रस्तावित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1995 के रूप में संसदीय प्रक्रिया की पूर्णतः इतम अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1995

[उत्तर प्रदेश अधिसूचना संख्या 15 सन् 1995]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के विधायी संसद में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।
- (2) यह 28 दिसम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुआ तमसा जायेगा।

संशोधित अधिनियम, 1995

संश्लिप्त नाम और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3
1982 के
अध्याय का
विषय

धारा 1 का
विषय
धारा 2 का
विषय

2- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के, जिसे प्रायः मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक में, शब्द "सेवा चयन बोर्ड" के स्थान पर शब्द "सेवा आयोग" रख दिए जायेंगे।

3- मूल अधिनियम की धारा 1 में उपधारा (1) में शब्द "सेवा चयन बोर्ड" के स्थान पर शब्द "सेवा आयोग" रख दिए जायेंगे।

4- मूल अधिनियम की धारा 2 में :-
(क) शब्द (क) निकाल दिया जायेगा;
(ख) इस प्रकार निकाले गए शब्द (क) के परचात् निम्नलिखित शब्द बड़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-
" (ख) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तत्समय अध्यक्ष के कर्तव्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है ;
(ग) 'आयोग' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग से है ;"
(घ) शब्द (घ) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिया जाएगा, अर्थात् :-
" (घ) 'सदस्य' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत आयोग का अध्यक्ष भी है ;"
(ङ) शब्द (ङ) निकाल दिया जायेगा ;
(च) इस प्रकार निकाले गए शब्द (ङ) के परचात् निम्नलिखित शब्द बड़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-
" (च) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;
(छ) 'अधिनियम' का तात्पर्य धारा 34 के अधीन बनाए किसी अधिनियम से है ;"

5- मूल अधिनियम की धारा 2 के परचात् निम्नलिखित शब्द बड़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-
" अध्याय-दो
आयोग की स्थापना और कृत्य
(1) एतदन्तर्गत अधिनियम द्वारा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त आयोग की नियुक्ति करे, एक आयोग स्थापित किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग कहलायेगा।
(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा। यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में शक्ति का प्रयोग करेगा और इसका मुख्यालय इलाहाबाद में होगा।
(1) आयोग में एक अध्यक्ष और छः से अधिक अन्य सदस्य होंगे जो, उपधारा 2 के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे।
(2) अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जायेंगे, जो-
(क) राज्य सरकार की राय में, निर्यात शिक्षाविद् रहे हों, या जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतः योगदान दिया हो; या
(ख) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में प्राचार्य के रूप में या ऐसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय में, दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए, प्राचार्य के रूप में कार्य किया हो; या
(ग) प्रदेश की न्यायिक, प्रशासनिक या शिक्षा सेवा में, दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए, अद्वैत अधिकारी के रूप में कार्य किया हो; या

अध्याय दो और
धारा 3 से 11
का बर्णना जाना

11

8
ब
न

9-—श्रायोग को निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

- (क) श्रध्यापकों को भर्ती और पबोन्नति की रीति से शक्ति और सम्बन्धित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना; कर्तव्य
- (ख) श्रध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए श्रध्यापियों का साक्षात्कार करना और चयन करना;
- (ग) श्रध्यापकों (ख) में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना;
- (घ) चयन किए गए श्रध्यापियों की नियुक्ति और उनकी पबोन्नति के सम्बन्ध में सिफारिश करना;
- (ङ) श्रध्यापकों की पबचयुति, हटाए जाने या पंक्तिचयुति से सम्बन्धित विषयों में प्रस्तावकों को स्लाह देना;
- (च) श्रध्यापक वर्ग की सदस्य संख्या और श्रध्यापकों की नियुक्ति, पबोन्नति, पबचयुति, पब से हटाने, सेवा समाप्ति या पंक्तिचयुति के सम्बन्ध में नियतकान्ति विवरणियाँ या श्रध्या सूचनाएँ संस्थाओं से प्राप्त करना;
- (छ) वि. (जी) की उपलब्धियाँ और यात्रा भत्ते और श्रध्या भत्ते नियत करना;
- (ज) श्रायोग में विहित तिथि का प्रबन्ध करना; ॥
- (झ) ऐसे श्रध्या कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी श्रध्या शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी विहित की जायें, या जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन प्रपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए श्रानु-भक्तिक या सहायक हों।

- 10-—(1) किसी श्रध्यापक की नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिए प्रबन्धतंत्र विद्यमान या भर्ती के वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की संख्या चयन की प्रक्रिया और, संस्था के प्रधान के पद से भिन्न पद की स्थिति में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (श्रानुसूचित जातियों, श्रानुसूचित जन-जातियों और श्रध्या पिछड़े वर्गों के लिए श्रध्यापक) अधिनियम, 1994 के श्रानुसार श्रानुसूचित जातियों, श्रानुसूचित जन-जातियों और श्रध्या पिछड़े वर्गों के श्रध्यापियों के लिए श्रध्यापित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या को श्रध्यापित करेगा और रिक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यम से, जैसा विहित किया जाय, श्रायोग को श्रध्यापित करेगा।
- (2) श्रध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए श्रध्यापियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।
- परन्तु श्रायोग प्रतिमासाली व्यक्तियों को आमंत्रित करने की दृष्टि से उपधारा (1) के अधीन श्रध्यापित रिक्तियों का राशय में श्रध्यापक प्रचार करेगा।

- 11-—(1) श्रायोग, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रिक्त के श्रध्यापित किए जाने के पश्चात् यथाशक्य श्रायोग श्रध्यापियों का साक्षात्कार श्रध्यापियों का करेगा और जो नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाए जायें, उनका पंक्त तैयार करेगा।
- (2) श्रायोग उपधारा (1) में निम्नलिखित धारा 10 की उपधारा (1) में निम्नलिखित अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसी रीति से जैसा विहित की जाय, श्रध्यापित करेगा।

- (3) उपधारा (2) के अधीन पंक्त प्राप्त होने के पश्चात् संबद्ध अधिकारी या प्राधि-कारी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन श्रध्यापित रिक्तियों के सम्बन्ध में संस्था के प्रबन्धतंत्र की चयन किए गए श्रध्यापियों के नाम विहित रीति से सूचित करेगा।
- (4) प्रबन्धतंत्र, ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की श्रध्यापियों की प्रतीत ऐसे चयनित श्रध्यापियों को, नियुक्ति-पत्र जारी करेगा।
- (5) जहाँ ऐसा चयनित श्रध्यापियों नियुक्ति-पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसे बड़ाए गए समय के भीतर जैसा प्रबन्धतंत्र इस निमित्त स्वीकार करे ऐसी संस्था में पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है या जहाँ ऐसा श्रध्यापियों नियुक्ति के लिए श्रध्यापक उपलब्ध नहीं है, वहाँ संबद्ध अधिकारी या प्राधिकारी प्रबन्धतंत्र के श्रानुरोध पर श्रायोग द्वारा उपधारा (2) के अधीन श्रध्यापित पंक्त से नया नाम या नए नाम, विहित रीति से सूचित करेगा।

6- मूल अधिनियम को अध्याय-तीन जिसमें धारा 12, 12-क, 12-ख, 12-ग, 13, 14, 15, 16 और 15-ख दी गई है निकास दिया जायगा।

अध्याय-तीन और धारा 12 से 15-ख का निकास जाना

7- मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (1) में-

धारा 16 का संशोधन

(क) शब्द, अंक और अक्षर "किन्तु धारा 21-ख" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "किन्तु धारा 18, 21-ख" रख दिये जायेंगे।

(ख) शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा प्रायोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धसूत्र द्वारा बोर्ड की सिफारिश पर ही की जायेंगी।" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धसूत्र द्वारा प्रायोग की सिफारिश पर ही की जाएगी।" रख दिए जायेंगे।

(ग) किसी परस्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परस्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-
"परस्तुक यह भी कि सेवा कोल में मृत किसी अध्यापक का या किसी संस्था के अध्यक्ष की पदोन्नति, जो इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन विहित प्रकृतियों से होती है, उत्तर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन बनाए गए अधिनियमों के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक प्रवृत्त में अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।"

8- मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1) में, शब्द "अध्याय तीन" के स्थान पर शब्द "अध्याय दो" रख दिए जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

9- मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

धारा 18 का प्रतिस्थापन

"18--(1) जहाँ प्रबन्धसूत्र ने धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार प्रायोग को किसी रिक्ति की सूचना दी हो, और किसी अध्यापक का पद वास्तव में तीन मास से अधिक रिक्त रहा हो, या प्रबन्धसूत्र इस धारा में एतदपश्चात् उपस्थित रीति से, किसी अध्यापक को चुनने या तदर्थ प्राधार पर सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा, नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक से भिन्न किसी अध्यापक को, जिसे सी. टी. द्वारा नियुक्त किया जाना हो, उपधारा (8) में निविष्ट चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जा सकता है।

(3) प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक से भिन्न किसी अध्यापक को, जिसे पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाना हो-

(क) प्रबन्धसूत्र प्रोवें में किसी रिक्ति के मासों में, विहित प्रकृतियों पर प्रशिक्षित स्नातक प्रोवें में श्रेष्ठतम अध्यापक की प्रबन्धता के रूप में;

(ख) प्रशिक्षित स्नातक प्रोवें में किसी रिक्ति के मासों में, विहित प्रकृतियों पर प्रोवें में सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग प्रोवें में श्रेष्ठतम अध्यापक की प्रशिक्षित स्नातक प्रोवें में अध्यापक के रूप में;

विहित रीति से पदोन्नति करके नियुक्त किया जा सकता है।

(4) प्रधानाचार्य के पद में किसी रिक्ति की प्रबन्धता प्रोवें में श्रेष्ठतम अध्यापक की पदोन्नति करके भरा जा सकता है।

(5) प्रधान अध्यापक के पद में किसी रिक्ति की प्रशिक्षित स्नातक प्रोवें में श्रेष्ठतम अध्यापक की पदोन्नति करके भरा जा सकता है।

(6) उपधारा (2) और (3) के अधीन नियुक्तियों करने के प्रयोजन के लिए प्रबन्धसूत्र रिक्तियों की संख्या और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (समुचित जातियों), समुचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए (प्रारक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार समुचित जातियों, समुचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अध्यापियों के लिए प्रारक्षण को जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी व्यवधारित करेगा और उसके पश्चात् यथाशक्य तुरीय सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों जिसे विधानसभे निरीक्षक को सूचित करेगा और यदि प्रबन्धसूत्र रिक्तियों को सूचित करने में विफल रहता है और अध्यापक का पद वास्तव में तीन मास से अधिक रिक्त

रहता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जैसा कि निदेशक जारी करे, ऐसी संस्था से या अपने अभिलेख से सत्यापन के पश्चात् स्वयं ऐसी रिक्तियों को अध्यापित कर सकता है।

(7) जिला विद्यालय निरीक्षक, उपधारा (6) के अधीन, यथास्थिति, रिक्तियों की सूचना की प्राप्ति पर या रिक्तियों का अध्यापन करने के पश्चात्, सम्बन्ध में प्रचारी उपस्थित निदेशक को रिक्तियों की सूचना अध्यापित कर देगा, जो, इन्टरमीडिएट विद्यालय अधिनियम, 1921 या लघु अधिनियम द्वारा विनियमों के अधीन विहित नहीं हुए रखने वाले विनियमों से, प्रदानाचार्य या प्रबन्धाध्यापक से भिन्न, अध्यापकों के पर पर तब तक नयुक्ति के लिए ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा।

(8) (क) प्रत्येक सम्भाग के लिए सीधी जर्नी द्वारा तब तक नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे--

- (एक) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक;
- (दो) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक (द्वितीय);
- (तीन) सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैथिक);
- सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक में जो इच्छुक होगा वह सम्मिलित होगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति प्रत्यर्थियों का चयन करेगी, चयनित प्रत्यर्थियों को सूची तैयार करेगी, उन्हें संस्थाओं की प्राबन्धित करेगी और उपधारा (2) के अधीन नियुक्ति के लिए प्रबन्धतंत्र को उनके नाम की सिफारिश करेगी।

(ग) प्रत्यर्थियों के चयन के लिए सापेक्ष और प्रक्रिया और चयनित प्रत्यर्थियों को सूची तैयार करने की और संस्थाओं को उनके प्राबन्धन की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।

(9) उपधारा (1) के अधीन तब तक अध्यापक को प्रत्येक नियुक्ति उस दिन तक से प्रभावित हो जाएगा जब वह प्रत्यर्थियों की सिफारिश प्रायोग द्वारा की गई हो, कार्य प्रारंभ कर ले।

(10) धारा 21-घ के उपबन्ध, प्रयासपूर्ण परिवर्तन सहित, ऐसे अध्यापकों पर लागू होंगे जिन्हें इस धारा के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किया जाना हो।

धारा 19 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 19 में--

- (क) शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "प्रायोग" रख दिया जायगा;
- (ख) शब्द और अंक "धारा 14" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 9" रख दिए जायेंगे।

धारा 20 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 20 में, शब्द "बोर्ड" द्वारा इस निम्नलिखित किसी शक्ति के स्थान पर शब्द "प्रायोग" के संक्षेप या प्रायोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति" रख दिए जायेंगे।

धारा 21 का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 21 में, शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "प्रायोग" रख दिया जायगा।

धारा 22, 23 और 26 का संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 22, 23 और 26 में, शब्द "बोर्ड", जहाँ कहीं भी प्रायोग हो, के स्थान पर शब्द "प्रायोग" रख दिया जायगा।

धारा 27 का प्रतिस्थापन

14--मूल अधिनियम की धारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्--
 "27--प्रायोग के सभी प्रादेश और विनियम धारा 8 के अधीन नियुक्त सचिव या प्रादेशीय प्रायोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणिकरण अधिप्रमाणित किए जायेंगे।"

धारा 28 का संशोधन

15--मूल अधिनियम की धारा 28 में, शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "प्रायोग" रख दिया जायगा।

नई धारा 29 का बढावा जाना

16--मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढा दी जाएगी, अर्थात्--
 "29--प्रायोग धारा 34 के अधीन बनाए गए विनियम द्वारा अपने सम्बन्ध में अपने किसी सचिव या अधिकारी को प्रायोग द्वारा या प्रायोग में किए गये अध्यापक कार्य के सामान्य अधिदेश और उनके सम्बन्ध में निदेश देने की अपनी शक्ति, जिसके अन्तर्गत कार्यालय के दायरत्व और प्रायोग के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेश
 अध्यापक
 संघ
 संघ 195
 उत्तर प्रदेश
 अध्यापक
 संघ 195

प्रशासन को सम्बन्ध में किए गए व्यव. से सम्बन्धित शक्ति को प्रत्याभोजित कर सकता है।"

मूल अधिनियम की धारा 32 में, शब्द "या इसके अधीन बनाए गए नियमों" के स्थान पर शब्द "या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों" रख दिए जायेंगे। धारा 32 का संशोधन

18--मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (1) में, परन्तु के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात्—
"परन्तु ऐसा कोई प्रादेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के तिनक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जाएगा।"

धारा 33 का संशोधन

19--मूल अधिनियम की धारा 33-अ में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (बी) में, शब्द और शंक "जैसी कि वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा जिनके पूर्व की" के स्थान पर शब्द और शंक "जैसी कि वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के पूर्व की" रख दिए जायेंगे। धारा 33-अ का संशोधन

20--मूल अधिनियम की धारा 33-अ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—
"34--(1) आयोग चयन करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए, फीस विहित करने हेतु और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के लिए आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बना सकता है या उन्हें संशोधित कर सकता है।
परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रथम विनियम राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा बनाए जायेंगे।
(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम, इस अधिनियम या धारा 35 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से प्रसंगत नहीं होंगे।"

धारा 33-अ का संशोधन

नई धारा 34 का बढ़ावा जाना

21--मूल अधिनियम की धारा 12 के, जैसी कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व की, अधीन निर्धारित निकाय के रूप में गठित माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, ऐसे प्रारम्भ पर विद्यमान हो जायवा और ऐसे विद्यमान पर,—
(क) ऐसे बोर्ड की सभी संपत्तियां और परिणवतियां और ऐसे बोर्ड के सभी व्यय वाशिल और बाध्यता, चाहे किसी संविदा के अधीन हो या अन्यथा हों, मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित आयोग को अन्तर्गत हो जायेंगी;
(ख) ऐसे बोर्ड में प्रतिनियुक्त पर काम करने वाले सभी व्यक्ति अपने मूल विभागों में प्रत्यागत हो जायेंगे;
(ग) ऐसे बोर्ड के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवाएं मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित आयोग को अन्तर्गत हो जायेंगी;
(घ) मूल अधिनियम के दायम तौर को, जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व था, अधीन ऐसे बोर्ड के समस्त सम्बन्धित कोई विषय और मूल अधिनियम की धारा 21 के अधीन ऐसे बोर्ड के समस्त सम्बन्धित कोई सम्बन्ध मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित आयोग को अन्तर्गत हो जाएगा।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 तन् 1995 उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं 0 1 तन् 1994

22--(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निम्नलिखित अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा पचासशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हुए कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा पचासशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन हुए कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध तभी सार्वजनिक समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और प्रपवाध

प्रासा से,
नरेश कुमार नारंग,
प्रमुख सचिव।

No. 1477 (2)/XVII-V-1-1(KA)12-1995

Dated Lucknow, August 8, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board (Sansodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 4, 1995.

**THE UTTAR PRADESH SEPCONDARY EDUCATION SERVICES
SELECTION BOARDS (AMENDMENT) ACT, 1995**

(U. P. Act. No. 15 of 1995)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards Act, 1982

IT IS HEREBY enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and
Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 28, 1994.

Amendment of
long title of U.P.
Act no. 3 of 1982

2. In the long title of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act, for the words 'Services Selection Boards' the words 'Services Commission' shall be substituted.

Amendment of
section 1

3. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words 'Services Selection Boards' the words 'Services Commission' shall be substituted.

Amendment of
section 2

4. In section 2 of the principal Act,—

(a) clause (a) shall be omitted;

(b) after clause (a) as so omitted, the following clauses shall be inserted, namely:—

“(b) ‘Chairman’ means the Chairman of the Commission and includes any other person performing, in the absence of the Chairman, for the time being, the functions of the Chairman;

(c) ‘Commission’ means the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission established under section 3;”;

(c) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—

“(g) ‘Member’ means a member of the Commission and includes its Chairman;”;

(d) clause (h) shall be omitted;

(e) after clause (h) as so omitted, the following clauses shall be inserted, namely:—

“(hh) ‘backward classes of citizens’ means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994;

(i) ‘regulation’ means any regulation made under section 34;”.

Insertion of
Chapter II and
sections 3 to 11

5. After section 2 of the principal Act, the following Chapter containing sections 3 to 11 shall be inserted, namely:—

“CHAPTER II,

ESTABLISHMENT AND FUNCTIONS OF THE COMMISSION.

3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification appoint in this behalf, there shall be established a Commission to be called the “Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission”.

(2) The Commission shall be a body corporate. It shall exercise powers throughout Uttar Pradesh and its headquarters shall be at Allahabad.

(1) The Commission shall consist of a Chairman and not more than six other members who shall, subject to subsection (2), be appointed by the State Government.

(2) The Chairman and members shall be appointed from amongst the persons who have—

(a) been in the opinion of the State Government, an eminent educationist or have made valuable contributions in the field of education; or

(b) worked as a Professor in any University established by law in Uttar Pradesh or as a Principal of any College recognised by or affiliated to such University for a period of not less than ten years; or

(c) worked as a senior officer in the Judicial, Administrative or Education Service of the State for a period of not less than ten years; or

(d) worked as a Principal of any Institution for a period of not less than fifteen years.

(3) Every appointment under this section shall take effect from the date on which it is notified by the State Government.

(1) Subject to the provisions of this Act, every Member shall hold office for a term of four years.

(2) No person shall be a member for more than two consecutive terms.

(3) A member may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government, but he shall continue in office until his resignation is accepted by the State Government.

(4) The office of the members shall be whole time and terms and conditions of their service shall be such as the State Government may by order, direct.

(5) Notwithstanding anything contained in this section, no person shall be appointed or continue as a member if he has attained the age of sixty two years.

(1) The State Government may, by order, remove from office any member, if he—

(a) is adjudged an insolvent; or
(b) engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or

(c) is, in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or of proved misconduct; or

(d) incurs any disqualification under this Act or the rules made thereunder.

Explanation—Where a member becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of any institution or participates in any way in the profits thereof or in any benefit or emolument arising therefrom, otherwise than a member, he shall, for the purpose of clause (c), be deemed to be guilty of misconduct.

(2) The procedure for the investigation and proof of misconduct under this section shall be such as may be prescribed.

7. The Commission may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations made under section 34, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provisions of this Act.

8. (1) The Secretary of the Commission shall be appointed by the State Government on deputation for a term not exceeding five years and other conditions of service shall be such as the State Government may, by order, determine.
- (2) Subject to such directions as may be issued by the State Government in this behalf, the Commission may appoint such other employees as it may think necessary for the efficient performance of its functions under this Act and on such terms and conditions of service as the Commission thinks fit.
9. The Commission shall have the following powers and duties Powers and duties of Commissions namely :—
- to prepare guidelines on matters relating to the method of recruitment and promotion of teachers;
 - to hold interviews and make selection of candidates for being appointed as teachers;
 - to select and invite experts for the purposes specified in clause (b);
 - to make recommendations regarding the appointment of selected candidates and their promotion;
 - to advise the Management in matters relating to dismissal, removal or reduction in rank of teachers;
 - to obtain periodical returns or other informations from institutions regarding strength of the teaching staff and the appointment, promotion, dismissal, removal, termination or reduction in rank of teachers;
 - To fix the emoluments and travelling and other allowances of the experts;
 - to administer the funds placed at the disposal of the Commission;
 - to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed or as may be incidental or conducive to the discharge of its functions under this Act or the rules or regulations made thereunder.
10. (1) For the purpose of making appointment of a teacher, the management shall determine the number of vacancies existing or likely to fall vacant during the year of recruitment and in the case of a post other than the post of Head of the Institution, also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and notify the vacancies to the Commission in such manner and through such officer or authority as may be prescribed.
- (2) The procedure of selection of candidates for appointment to the post of teachers shall be such as may be prescribed :
- Provided that the Commission shall, with a view to inviting talented persons, give wide publicity in the State to the vacancies notified under sub-section (1).
11. (1) The Commission shall, as soon as may be, after the vacancy is notified under sub-section (1) of section 10, hold interviews of the candidates and prepare a panel of those found most suitable for appointment.
- (2) The panel referred to in sub-section (1) shall be forwarded by the Commission to the officer or authority referred to in sub-section (1) of section 10 in such manner as may be prescribed.
- (3) After the receipt of the panel under sub-section (2), the officer or authority concerned shall in the prescribed manner intimate the Management of the Institution the names of the selected candidates in respect of the vacancies notified under sub-section (1) of section 10.

(4) The management shall, within a period of one month from the date of receipt of such intimation, issue appointment letter to such selected candidate.

(5) Where such selected candidate fails to join the post in such institution within the time allowed in the appointment letter or within such extended time as the Management may allow in this behalf, or where such candidate is otherwise not available for appointment, the officer or authority concerned may, on the request of the Management, intimate, in the prescribed manner, fresh name or names from the panel forwarded by the Commission under sub-section (2).

6. Chapter III of the principal Act containing sections 12, 12-A, 12-B, 12-C, 13, 14, 15, 15-A and 15-B shall be omitted.

Omission of Chapter III and sections 12 to 15-B
Amendment of section 16

7. In section 16 of the principal Act, in sub-section (1)—

(a) for the words and figures "subject to the provisions of section 21-B" the words and figures "subject to the provisions of sections 18, 21-B" shall be substituted;

(b) for the words and figures "Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992 be made by the Management only on the recommendation of the Board," the words and figures "Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Act, 1995 be made by the Management only on the recommendation of the Commission," shall be substituted;

(c) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely—

"Provided also that the dependent, of a teacher or other employee of an institution dying in harness, who possesses the qualifications prescribed under the Intermediate Education Act, 1921 may be appointed as teacher in Trained Graduate's Grade in accordance with the regulations made under sub-section (4) of Section 9 of the said Act."

8. In Section 17 of the principal Act, in sub-section (1), for the word and figure "Chapter III" the word and figure "Chapter II" shall be substituted.

Amendment of section 17

9. For Section 18 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely—

Substitution of section 18

18. (1) Where the Management has notified a vacancy to the Commission in accordance with sub-section (1) of Section 10 and the post of a teacher actually remained vacant for more than two months, the Management may appoint by direct recruitment or promotion a teacher on purely *ad hoc* basis, in the manner hereinafter provided in this section.

(2) A teacher other than a Principal or Headmaster, who is to be appointed by direct recruitment may be appointed on the recommendation of the Selection Committee referred to in sub-section (8).

(3) A teacher other than a Principal or Headmaster, who is to be appointed by promotion, may in the prescribed manner be appointed by promoting the senior most teacher, possessing prescribed qualifications—

(a) in the trained graduate's grade, as a lecturer, in the case of a vacancy in the lecturer's grade;

(b) in the Certificate of Teaching grade, as teacher, in the trained graduate's Grade, in the case of a vacancy in the Trained graduate's grade.

(4) A vacancy in the post of a Principal may be filled by promoting the senior most teacher in the lecturer's grade.

(5) A vacancy in the post of a Headmaster may be filled by promoting the senior most teacher in the trained graduate's grade.

(6) For the purposes of making appointments under sub-sections (2) and (3), the Management shall determine the number of vacancies, as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes

and Other Backward Classes of citizen in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and, as soon as may be thereafter, intimate the vacancies to be filled by direct recruitment to the District Inspector of Schools and if the Management fails to intimate the vacancies and the post of a teacher has actually remained vacant for more than three months, the District Inspector of Schools may, subject to such directions as may be issued by the Director and after verification from such institution or from his own record, determine such vacancies himself.

(7) The District Inspector of Schools shall, on receipt of intimation of vacancies or as the case may be, after determining the vacancies under sub-section (6), forward the same to the Deputy Director of Education incharge of the Region, who shall invite applications from the persons possessing qualifications prescribed under the Intermediate Education Act, 1921 or the regulations made thereunder, for *ad hoc* appointment to the post of teachers other than Principal or Head Master in such manner as may be prescribed.

(8) (a) For each region there shall be a Selection Committee for selection of candidates for *ad hoc* appointment by direct recruitment comprising—

- (i) Regional Deputy Director of Education ;
- (ii) Regional Deputy Director of Education (Second) ;
- (iii) Regional Assistant Director of Education (Basic).

The Regional Deputy Director of Education who is senior shall be the Chairman.

(b) The Selection Committee constituted under clause (a) shall make selection of the candidates, prepare a list of the selected candidates, allocate them to the Institutions and recommend their names to the Management for appointment under sub-section (2).

(c) The criteria and procedure for selection of candidates and the manner of preparation of list of selected candidates and their allocation to the Institution shall be such as may be prescribed.

(9) Every appointment of an *ad hoc* teacher under sub-section (1) shall cease to have effect from the date when the candidate recommended by the Commission joins the post.

(10) The provisions of section 21-D shall *mutatis mutandis* apply to the teachers who are to be appointed under the provisions of this section."

Amendment of section 19

10. In section 19 of the principal Act,—

(a) for the word "Board" the word "Commission" shall be substituted.

(b) for the word and figure "section 14" the word and figure "section 9" shall be substituted.

Amendment of section 20

11. In section 20 of the principal Act, for the words "Any person authorised in this behalf by the Board" the words "The Secretary of the Commission or any other person authorised by the Commission" shall be substituted.

Amendment of section 21

12. In section 21 of the principal Act, for the word "Board" the word "Commission" shall be substituted.

Amendment of sections 22, 23 and 26

13. In sections 22, 23 and 26 of the principal Act, for the words "the Board" wherever occurring, the words "the Commission" shall be substituted.

Substitution of section 27

14. For section 27 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"27. All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary appointed under section 8 or any other officer authorised by the Commission."

Authentication of the orders

15. In section 28 of the principal Act, for the words "the Board" the words "the Commission" shall be substituted. Amendment of section 28

16. After section 28 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :— Insertion of new section 29

"29. The Commission may, by regulation made under section 34, delegate to its Chairman or any of its Members or officers, its power of general superintendence and direction over the business transacted by or in the Commission including the powers with regard to the expenditure incurred in connection with the maintenance of the office and internal administration of the Commission."

17. In section 32 of the principal Act, for the words "or the rules thereunder" the words "or the rules or regulations made thereunder" shall be substituted. Amendment of section 32

18. In section 33 of the principal Act, in sub-section (1), for the proviso the following proviso shall be substituted, namely :— Amendment of section 33

"Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Act, 1995."

19. In section 33-B of the principal Act, in sub-section (1) in clause (a), in sub-clause (iii), for the words and figures "as it stood before its omission by the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992" the words and figures "as it stood before its substitution by the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Second Amendment) Act, 1995" shall be substituted. Amendment of section 33-B

20. After section 33-B of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :— Insertion of new section 34

"34. (1) The Commission may, with the previous approval of the State Government, make or amend regulations prescribing fees for holding selections, for holding interviews and laying down the procedure to be followed by the Commission for discharging its duties and performing its functions under this Act."

Provided that the first regulation under this sub-section shall be made by the State Government by notification in the Gazette.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act or the rules made under section 35."

21. The Secondary Education Selection Boards constituted as body corporate under section 12 of the principal Act as it stood immediately before the commencement of this Ordinance, shall upon such commencement stand dissolved, and upon such dissolution— Transitory provisions

(a) all properties and assets of such Boards and all debts, liabilities and obligations of such Boards, whether contractual or otherwise, shall stand transferred to the Commission established under section 3 of the principal Act;

(b) all persons serving on deputation in such Boards shall revert to their parent departments;

(c) the service of every whole time employee of such Boards shall stand transferred to the Commission established under section 3 of the principal Act;

(d) any matter pending before such Boards under Chapter III of the principal Act as it stood immediately before the commencement of this Act and any reference pending before such Boards under section 21 of the principal Act shall stand transferred to the Commission established under section 3 of the principal Act,

Repeal and
savings

22. (1) The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Ordinance, 1995 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Secondary Education Services selection Board (Amendment) Ordinance, 1994, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U. P. Ordinance
no. 13 of
1995

U. P. Ordinance 31
1994

By Order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.